पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की विविध अपील सं. 461

==========

श्वेता सिंह, पत्नी- प्रणव कुमार, निवासी- गांव-जोगियारा, थाना- जाले, जिला-दरभंगा, वर्तमान में सी/ओ और डी/ओ बिजय कुमार सिंह हाउस सं. 33, किदवईपुरी, थाना- कोतवाली, जिला-पटना।

.... अपीलार्थी/याचिकाकर्ता

बनाम

प्रणव कुमार सिंह, पुत्र- गणेश सिंह, निवासी- गाँव-जोगियारा, थाना- जाले, जिला- दरभंगा

.... उत्तरदाता/विरोधी पक्ष

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री साहिल कुमार

उत्तरदाताओं के लिए कुमारः श्री

==========

विचाराधीन मुद्दा: *क्या पारिवारिक अदालत ने आदेश पारित करने में गलती की है और अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों पर ध्यान नहीं दिया है, जबकि वाद की जड़ यह है कि अपीलकर्ता-पत्नी के पास अलग रहने का कारण है।*

वर्तमान अपील को वैवाहिक (तलाक) वाद में विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना द्वारा पारित दिनांक 01.05.2023 के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा तलाक की डिक्री देने के लिए वैवाहिक मामला दायर किया

गया है। अपीलकर्ता ने तलाक की याचिका दायर की है जहां उसने अपने पति के आचरण के बारे में वैवाहिक विवाद पर जोर दिया है कि उसने वैवाहिक घर कैसे छोड़ दिया है, हालांकि, वह शामिल हो गई है लेकिन आखिरकार वह चली गई और वह अपना जीवन असमंजस में जारी नहीं रखना चाहती है। आने वाला हर समय. जीवन की अवधि का विस्तार नहीं किया जा सकता है और उक्त अवधि में, उसने तलाक की याचिका पर मुकदमेबाजी में कम से कम छह साल बिताए हैं और पति ने उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का ध्यान नहीं रखा है और अपीलकर्ता/पत्नी के प्रति पति की उदासीनता के कारण मानसिक पीड़ा हो रही है। इतने वर्ष एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने का उदाहरण नहीं है, बल्कि एक रिश्ते को बोझिल इकाई के रूप में ढोया जा रहा है। ऐसे वैवाहिक जीवन के लिए क्रूरता के आधार पर तलाक एक उपाय है।

निर्णित: वर्तमान वाद में, संबंधित अदालत ने तलाक की डिक्री को अस्वीकार करने में अनौपचारिक दृष्टिकोण अपनाया क्योंकि संबंधित अदालत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तलाक की याचिका दायर करने की तारीख से या नोटिस जारी होने के बाद, प्रतिवादी-पति ने बचाव के लिए कोई कष्ट नहीं उठाया है। यहां तक कि उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर करके अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है और आदेश पारित करते समय संबंधित अदालत ने अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रखा है। वाद की जड़ यह है कि अपीलकर्ता-पत्नी के पास अलग रहने का कारण है जिसका खंडन नहीं किया गया है और यही बात अपीलकर्ता के पिता ने भी दोहराई है। प्रतिवादी पति 20.03.2015 से शारीरिक रूप से अनुपस्थित है और ऐसी स्थिति मानसिक क्रूरता को जन्म देती है।

वैवाहिक जीवन में तलाक के आधार के रूप में क्रूरता - चर्चा की गई [पैरा 17-23]

डॉ. एन.जी. दास्ताने बनाम श्रीमती एस. दास्ताने एआईआर 1975 एससी 1534 में; शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी (1988) 1 एससीसी 105; 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1127 रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी ; समर घोष बनाम जया घोष (2007) 4 एससीसी 511 - संदर्भित [पैरा 17-23]

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री**

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे

सी.ए.भी निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे)

तारीखः 12-09-2024

वर्तमान अपील को 2018 के वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 04 में पटना के विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय दिनांक 01.05.2023 और डिक्री दिनांक 09.05.2023 के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा और जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा तलाक की डिक्री देने के लिए दायर वैवाहिक वाद को खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में कहा गया है कि अपीलार्थी के वाद का तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (ए) के तहत 03.01.2018 को तलाक की याचिका दायर की। प्रासंगिक तथ्यों को तलाक याचिका के आधार पर पेश किया जा रहा है जिसमें अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी का विवाह उत्तरदाता के संग दिनांकित 30.11.2024 को हिन्दू संस्कारों एवं अनुष्ठानों द्वारा हाउस सं. 33, किदवईपुरी, थाना - कोतवाली, जिला - पटना में संपन्न हुआ और यह अनुमान लगाया जाता है कि शादी के समय उत्तरदाता को 12 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी, टेलीविजन, फ्रिज, वाशिंग मशीन, अन्य आवश्यक वस्तुएं और दस लाख

रुपये जैसे उपहार दिए गए थे। यह दावा किया जाता है कि 01.12.2014 को अपीलार्थी दरभंगा जिले के जोगियारा गाँव, थाना - जाले में स्थित अपने पति के घर आई थी। यह आगे दावा किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने और अधिक दहेज की मांग करना शुरू कर दिया और उक्त मांग अपीलार्थी के माता-पिता द्वारा पूरी नहीं की जा रही थी, इसलिए प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर हमला किया जा रहा था और उसे 05.12.2014 को प्रत्यर्थी के घर से बाहर कर दिया गया था और यह दावा किया गया है कि विवाहिक संबंध नहीं हुआ थी। यह आगे दावा किया जाता है कि प्रतिवादी अपीलार्थी के माता-पिता द्वारा की गई बातचीत के आधार पर 17.01.2015 को अपीलार्थी को अपने साथ वापस ले आया। यह आगे दावा किया जाता है कि प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज की मांग के लिए अपीलार्थी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि प्रतिवादी ने अपीलार्थी/पत्नी द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद अपीलार्थी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। यह आगे दावा किया जाता है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी और परिवार के सदस्यों द्वारा 20.03.2015 को प्रत्यर्थी के घर से फिर से बाहर निकाल दिया गया था और तब से अपीलार्थी को अपीलार्थी के माता - पिता द्वारा किये गए प्रयासों के बावजूद कभी वापिस नहीं लाया गया। यह दावा किया जाता है कि 20.03.2015 के बाद से वह लगातार प्रतिवादी से अलग रह रही है। यह आगे दावा किया जाता है कि अक्टूबर, 2017 के महीने में अपीलार्थी के माता-पिता ने प्रत्यर्थी से संपर्क किया और उससे अपनी बेटी को अपने साथ रखने का अनुरोध किया, लेकिन प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी/पत्नी को रखने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इसलिए, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के खिलाफ क्रूरता की क्योंकि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा छोड़ दिया गया था क्योंकि 20.03.2015 से बिना किसी वैध कारण के और विवाह संपन्न नहीं हुआ था।

3. संबंधित अदालत द्वारा सारी प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद, प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ और तलाक के वाद का *एकतरफा* फैसला किया गया।

4. इस अदालत ने प्रतिवादी/पति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके खिलाफ सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जारी की हैं, लेकिन वह इस अदालत के समक्ष भी पेश नहीं हुआ।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान संबंधित अदालत ने तलाक की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए यातना के आरोप कानून में परिकल्पित क्रूरता के मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संबंधित अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि अदालत के समक्ष अपने बयान में, उसने कोई बयान नहीं दिया है कि उसकी विवाहिक संबंध नहीं हुआ है, इसलिए लगाए गए उक्त आरोप साबित नहीं किए जा सके। विद्वान परिवार न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के साक्ष्य से यह नहीं पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने ऐसी कोई स्थिति पैदा की जिससे वह अपने पति से अलग रहने के लिए मजबूर हो गई। उन्होंने आगे कहा कि 2018 के वैवाहिक तलाक वाद संख्या 04 में पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, अपीलार्थी ने वर्तमान विविध अपील दायर की है। अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि पारिवारिक मामलों में उचित संदेह से परे तथ्य को साबित करने के लिए प्रक्रिया की औपचारिकताओं का सख्ती से पालन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी का रवैया देखा जा सकता है कि अदालत द्वारा जारी पर्याप्त सेवा होने के बावजूद वह न तो निचली अदालत या इस अदालत के समक्ष पेश हुआ। इस तरह, प्रत्यर्थी/पति के असहयोगी रवैये को ध्यान में रखा जा सकता है कि उसका आचरण अपनी पत्नी को वैवाहिक घर में रखने के लिए उचित नहीं है क्योंकि वैवाहिक जीवन और कुछ नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन जीने के लिए दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ और अपीलार्थी द्वारा दिए गए किसी भी बयान से इनकार नहीं किया और अपीलार्थी और अन्य गवाह के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने अदालत के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है और उसने अपना साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है एवं कहा है

कि तलाक याचिका में दवा सत्य नहीं है एवं उसने कहा है कि तलाक याचिका में दावा सही है और उसने दोहराया है कि वह यातना के कारण अपने पति से अलग रह रही है और वह तलाक देने का इरादा रखती है क्योंकि उसका पति शराब पीने के बाद उस पर हमला करता था।

6. स्वयं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के दौरान तलाक याचिका के तर्क को दोहराया गया है। पीडब्लू-2 ने शादी और उपहार के संबंध में तलाक की याचिका को दोहराया और उसने पीडब्लू-1 के बयान की पुष्टि की है कि वह 17.12.2014 को अपने वैवाहिक घर में शामिल हुई थी, लेकिन प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंत में 03.01.2018 को तलाक का मामला दायर किया गया और दोनों 20.03.2015 के बाद से अलग रह रहे हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि तलाक याचिका का दावा सही है। इस तरह, दोनों गवाहों ने तथ्यों के संस्करण का समर्थन किया है जैसा कि तलाक याचिका में दोहराया गया है।

7. अपीलार्थी की ओर से दो गवाहों से पूछताछ की गई है। एडब्ल्यू-1 स्वयं अपीलार्थी है और एडब्ल्यू-2/विजय कुमार सिंह अपीलार्थी के पिता हैं। अपीलार्थी ने विवाह कार्ड भी दाखिल किया है जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिह्नित किया गया है और विवाह की युगल तस्वीर जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

8. अपीलार्थी की ओर से जाँच किए गए दो गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक है।

9. अपीलार्थी की जाँच 02.12.2019 को ए. डब्ल्यू.- 1 के रूप में की गई और उन्होंने शपथ पर बयान दिया है। मुख्य परीक्षण के दौरान, उसका साक्ष्य सटीक और संक्षिप्त होता है जिसमें चार पैराग्राफ होते हैं। पैरा 1 में, उसने कहा है कि अपीलार्थी ने पटना में हिंदू रीति-रिवाजों और संस्कारों के अनुसार 30.11.2014 को प्रत्यर्थी के साथ शादी की और उसे अपनी शादी से कोई समस्या नहीं है। उसने दोहराया है कि दस लाख रुपये नकद, 12 भर सोना, 500 ग्राम चांदी, टेलीविजन, फ्रिज और सभी घरेलू सामान उसके पिता द्वारा उसके ससुराल वालों को उपहार के रूप में दिए गए थे और शादी के बाद वह अपने पति के साथ 01.12.2014 को अपने

वैवाहिक घर गई थी। पैरा-2 में उसने कहा है कि वह अपने पति को तलाक देने का इरादा रखती है क्योंकि उसका पति शराब पीने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। वह उसे प्रताड़ित करता था और दहेज की मांग करता था और उसके माता-पिता और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, जिसके कारण उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। पैरा 3 में उसने कहा है कि वह यातना के कारण अपने पति से चार साल से अलग रह रही है। पैरा 4 में उसने कहा है कि तलाक याचिका में किया गया दावा सही है।

10. विजय कुमार सिंह, जो अपीलार्थी के पिता हैं, से ए. डब्ल्यू.-2 के रूप में 21.01.2021 को जाँच की गई है। उनके साक्ष्य भी बहुत सटीक और संक्षिप्त हैं। उनका साक्ष्य एक पैराग्राफ में दर्ज किया गया है। उन्होंने विवाह के तथ्य का समर्थन किया है और दोहराया है और कहा है कि अपीलार्थी उनकी बेटी है और उन उपहार वस्तुओं को भी दोहराया है जो विवाह के समय और विवाह के बाद जब वह ससुराल गई जहाँ प्रतिवादी और परिवार के सदस्यों ने दहेज की मांग की और अपीलार्थी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जिसके कारण वह 05.12.2014 को अपने मायके के पास वापस लौट आई। अपीलार्थी बातचीत के बाद 17.12.2014 को वैवाहिक गृह में शामिल हो गया और उसके बाद प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और वह यातना के कारण अपने पिता के घर/मायके वापस लौट आई। एडब्ल्यू-2 और उसके परिवार के सदस्यों ने प्रतिवादी को शांत करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और 03.01.2018 को तलाक का मामला दायर किया गया। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के वैवाहिक जीवन से कोई संतान नहीं था। मार्च, 2015 से अपीलार्थी और प्रत्यर्थी अलग रह रहे हैं। एडब्ल्यू-2 ने बताया है कि उक्त मामला दर्ज करने के पीछे का कारण प्रत्यर्थी की यातना के साथ-साथ शराब पीने की आदत थी। उन्होंने दोहराया है कि अपीलार्थी द्वारा दायर तलाक का दावा सही है।

11. एडब्ल्यू-1 और एडब्ल्यू-2 द्वारा दिए गए बयान से यह स्पष्ट है कि तलाक की याचिका 03.01.2018 को दायर की गई थी। विवाह के बाद अपीलार्थी 01.12.2014 को वैवाहिक

गृह में शामिल हुआ, लेकिन प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज के लिए अपीलार्थी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अपीलार्थी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था और अपीलार्थी और उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। अपीलार्थी ने सबूत के रूप में कहा है कि यद्यपि अपीलार्थी का साक्ष्य प्रस्तुत करने का एपिग्रामेटिक दृष्टिकोण तलाक याचिका के सार को दर्शाता है। एडब्ल्यू-2/अपीलार्थी के पिता ने विवाह के तथ्य को दोहराया है और इसी तरह, उन्होंने समर्थन और पुष्टि की है कि अपीलार्थी और प्रतिवादी यातना के कारण मार्च, 2015 से अलग रह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 17.12.2014 को, अपीलार्थी वैवाहिक गृह में शामिल हो गया था, लेकिन प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था और वह एडब्ल्यू-2 (अपीलार्थी के पिता) के घर वापस लौट आई। उन्होंने यह भी समर्थन किया है कि अपीलार्थी अपने पति से अलग रह रही है और एडब्ल्यू-1 और एडब्ल्यू-2 दोनों ने दावा किया है कि तलाक की याचिका सही है। इस तरह दोनों गवाहों ने तलाक की याचिका का समर्थन और पुष्टि की है।

12. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है, लेकिन प्रतिवादी संबंधित अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ। प्रत्यर्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इस अदालत द्वारा फिर से नोटिस की सेवा और नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा को ध्यान में रखा गया है, लेकिन प्रत्यर्थी इस अदालत के समक्ष भी पेश नहीं हुआ। संबंधित अदालत ने तलाक की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि अपीलकर्ता वाद को साबित करने में विफल रहा है। संबंधित अदालत ने तलाक याचिका को तकनिकी आधार पर खारिज किया है कि उसने अपने पति के क्रूर आचरण के संबंध में कभी भी किसी उपयुक्त मंच या थाने या किसी सक्षम अदालत के समक्ष कोई शिकायत नहीं की है। अपीलार्थी और अन्य गवाहों ने यह नहीं बताया है कि प्रतिवादी और परिवार के सदस्यों द्वारा क्या आचरण किया गया था जिसके द्वारा अपीलार्थी को प्रताड़ित किया जा रहा था। अपीलार्थी द्वारा दिया गया केवल बयान इस प्रभाव का था कि

प्रत्यर्थी शराब पीता था और अपीलार्थी द्वारा यह कभी नहीं बताया गया था कि प्रत्यर्थी शराब पीने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और यह नहीं पाया गया कि प्रत्यर्थी का लगातार किया गया आचरण अपीलार्थी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा था और पति और पत्नी के बीच उक्त आचरण का आरोप तुच्छ वाद के संबंध में विवाद के बराबर है और इसे क्रूरता के रूप में नहीं लिया जा सकता है, हालांकि तलाक याचिका में कहा गया है कि विवाहिक संबंध नहीं हुआ है, लेकिन साक्ष्य के दौरान, उसने यह नहीं कहा है कि विवाहिक संबंध नहीं हुआ है।

13. विवादित फैसले के अवलोकन से ही, अदालत ने पारिवारिक वाद के उस पहलू पर विचार नहीं किया है जिसमें सख्त सबूत को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है जहां याचिका में बताए गए तथ्यों की पुष्टि अपीलार्थी और अन्य गवाह द्वारा की जाती है। वाद का सार यह है कि अपीलार्थी क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग कर रहा है। उन्होंने अपनी शिकायत पारिवारिक न्यायालय के समक्ष रखी है जो तलाक से संबंधित पारिवारिक विवाद को संभाल रहा है और यह एक संवेदनशील मामला है। अदालत ने प्रतिवादी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पहले ही सभी प्रक्रियाएं जारी कर दी हैं, लेकिन प्रतिवादी इस अदालत या निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ और अपीलार्थी द्वारा अपनी तलाक याचिका में बताए गए तथ्य को प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, तो अदालत एक पक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। अदालत को तलाक की याचिका में बताए गए तथ्यों और पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूतों पर विचार करना होता है। वर्तमान वाद में, अपीलार्थी ने स्वयं कहा है कि वह वैवाहिक घर में शामिल हो गई है और उसके पास 20.03.2015 को वैवाहिक घर छोड़ने का कारण है और अन्य पक्ष द्वारा वैवाहिक जीवन को बहाल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है और वह 20.03.2015 के बाद से अलग रह रही है।

14. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वह 20.03.2015 के बाद से अपने पति से अलग रह रही है और 03.01.2018 को तलाक की याचिका दायर की गई थी और

तलाक की याचिका वर्ष 2023 में खारिज कर दी गई है जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि दोनों पक्ष 8 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। इस संदर्भ में, हम कह सकते हैं कि प्रतिवादी ने अलग होने की तारीख के बाद से अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए प्रयास नहीं किया है और दोनों गवाहों ने कहा है कि तलाक याचिका में किए गए दावे अपीलार्थी का सही दावा हैं। पारिवारिक मामलों में, प्रमाण को उचित संदेह से परे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन इसे संभावना की प्रधानता की श्रेणी में रखा जा सकता है।

15. वर्तमान विविध अपील दायर करने के समय अपीलार्थी की आयु 35 वर्ष है और तलाक याचिका दायर करने के समय उसकी आयु 30 वर्ष है और उसने प्रत्यर्थी के खिलाफ मुकदमा लड़ने में अपना बहुमूल्य और मूल्यवान समय खो दिया है, जिसे अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं है। पति होने के दायित्व से बचने के लिए, वह परिवार न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा।

16. वैवाहिक जीवन जहाँ दोनों पक्ष आम तौर पर एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जीते हैं। दोनों पक्ष एक-दूसरे की देखभाल करते हैं। कुछ झगड़ा हो सकता है लेकिन कहा जाता है कि झगड़ा उस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जहां इतने वर्षों तक किसी का दूसरे से कोई लेना-देना न हो। ऐसे वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जीवन के उद्देश्य का कोई अर्थ नहीं है जहां एक व्यक्ति दूसरे की देखभाल नहीं कर रहा है। कई मामलों में, वैवाहिक विवाद का पक्षकार कई मंचों पर मुकदमा करने में रुचि नहीं लेता है, उस स्थिति में, पक्षकार ने तलाक याचिका दायर करके वैवाहिक जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया जो वर्तमान वाद में बहुत प्रासंगिक है। अपीलार्थी ने तलाक की याचिका दायर की है जहाँ उसने अपने पति के आचरण के संबंध में वैवाहिक विवाद पर जोर दिया है कि कैसे उसने वैवाहिक घर छोड़ा है, यद्यपि वह वैवाहिक घर में शामिल हो गई है, लेकिन अंत में वह चली गई और वह आने वाले सभी समय में अपना जीवन अस्थिर जारी नहीं रखना चाहती है। जीवन की अवधि का विस्तार नहीं किया जा सकता है और उक्त अवधि में, उसने तलाक की याचिका के मुकदमे में कम-से-कम छह साल बिताए हैं

और पति ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का ध्यान नहीं रखा है और अपीलकर्ता/पत्नी के प्रति पति की उदासीनता के कारण इतने वर्षों से मानसिक पीड़ा हो रही है जो खुशहाल वैवाहिक जीवन नहीं जीने का एक उदाहरण है, बल्कि एक संबंध को बोझ वाली इकाई के रूप में ले जाया जा रहा है। ऐसे वैवाहिक जीवन के लिए तलाक क्रूरता के आधार पर उपाय है।

17. क्रूरता के आधार के अलोक में, **एआईआर 1975 एससी 1534** में प्रतिवेदित **डॉ. एन.जी. दास्ताने** बनाम **श्रीमती एस. दास्ताने** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या पाना आवश्यक है। "क्रूरता"शब्द की व्याख्या की गई है कि कौन का अधिनियम क्रूरता का गठन करता है, जो विवाह के विघटन का आधार है, उसे ऐसे चरित्र के जानबूझकर और अन्यायपूर्ण आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य को बुरी तरह या मानसिक रूप से खतरे में डालता है या इस तरह के खतरे की उचित आशंका को जन्म देता है। अधिनियम की धारा 10 (1) (बी) के तहत हिंदू विवाह अधिनियम के वैधानिक प्रावधान के तहत क्रूरता क्या है, यह इस कानून की अवधि पर निर्भर करता है, जो प्रदान करता हैः

> *"10. (1) विवाह के लिए कोई भी पक्ष, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न किया गया हो, जिला न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत यह प्रार्थना करते हुए कि इस आधार पर न्यायिक अलगाव, दूसरे पक्ष*
>
> *(बी) याचिकाकर्ता के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया है जिससे याचिकाकर्ता के मन में एक उचित आशंका पैदा हो कि याचिकाकर्ता के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या अहितकर होगा;"*

18. **1994 ए आई आर 710** में प्रतिवेदित **भी. भगत** बनाम **डी. भगत** के वाद में क्रूरता के पहलु का परीक्षण किया हो **(1988) 1 एस सी सी**105 में प्रतिवेदित **शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी** के वाद को संदर्भित करते हुए। हिंदू विवाह अधिनियम में "क्रूरता"शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसका उपयोग वैवाहिक कर्तव्यों या दायित्वों के संबंध में या उनके संबंध में मानव आचरण या व्यवहार के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (1) (आई-ए) में

किया गया है। यह एक आचरण का एक तरीका है जो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। यदि यह भौतिक है, तो यह तथ्य और डिग्री का सवाल है। यदि यह मानसिक है, तो क्रूर व्यवहार की प्रकृति और फिर जीवनसाथी के मन पर इस तरह के व्यवहार के प्रभाव के बारे में जांच शुरू होनी चाहिए। क्या यह उचित आशंका पैदा करता है कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या अहितकर होगा, अंततः, आचरण की प्रकृति और शिकायत करने वाले जीवनसाथी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

19. "क्रूरता"शब्द की व्याख्या पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का सार यह है कि इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए समझा और व्याख्या की जानी चाहिए कि पक्ष किस प्रकार के जीवन के आदी हैं; या उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों और उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें वे महत्व देते हैं। प्रत्येक वाद का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

20. **2023 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 1127** में प्रतिवेदित **रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी** वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पारित निराय उद्घृत करना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कि कंडिका 5,6, एवं 9 के उक्त निर्णय में न्यायलय ने निम्नवत अभिनिर्धारित की है :-

> "5. 1955 के अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत 'क्रूरता'शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, और इसलिए, न्यायालय को इसे उदारता और प्रासंगिक रूप से लागू करने के लिए एक बहुत व्यापक विवेकाधिकार देता है। एक वाद में जो क्रूरता है वह दूसरे के लिए समान नहीं हो सकती है। जैसा कि कहा गया है, उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर लागू किया जाना चाहिए।

6. विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल, (2012) 7 एस. सी. सी. 288 में यह न्यायालय पर्याप्त रूप से निर्धारित करता हैः

"22. "क्रूरता"अभिव्यक्ति का मानव आचरण या मानव व्यवहार के साथ एक अविभाज्य संबंध है। यह हमेशा उस सामाजिक स्तर या वातावरण पर निर्भर करता है जिसमें पक्ष शामिल होते हैं, उनके जीवन के तरीके, संबंध, स्वभाव और भावनाएं जो उनकी सामाजिक स्थिति से प्रभावित होती हैं।

9. "सामाजिक न्याय निर्णय"की इस अवधारणा को बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोंडसे (2014) 1 एस सी सी 188 के वाद में इस न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से पहल किया गया है:

"14. हाल ही में, इस दिशा में, इस बात पर जोर दिया जाता है कि अदालतों को "सामाजिक न्याय निर्णय"में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने होते हैं, जिसे "सामाजिक संदर्भ निर्णय"के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि केवल "प्रतिकूल दृष्टिकोण"बहुत उपयुक्त नहीं हो सकता है। समाज में कमजोर समूहों को विशेष सुरक्षा और लाभ देने वाले कई सामाजिक न्याय कानून हैं। प्रो.माधव मेनन ने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया हैः

"इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि 'सामाजिक संदर्भ न्यायनिर्णयन'अनिवार्य रूप से समानता न्यायशास्त्र का अनुप्रयोग है जैसा कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालतों के समक्ष प्रस्तुत असंख्य स्थितियों में विकसित किया गया है जहां असमान पक्षों को प्रतिकूल कार्यवाही में लागू किया जाता है और जहां अदालतों को समान न्याय देने के लिए कहा जाता है। असमान लड़ाई में गरीबों की अक्षमताओं को बढ़ाने वाली सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के अलावा, प्रतिकूल प्रक्रिया स्वयं कमजोर पक्ष के नुकसान के लिए काम करती है। ऐसी स्थिति में, न्यायाधीश को न केवल शामिल पक्षों की

असमानताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, बल्कि कमजोर पक्ष के प्रति सकारात्मक झुकाव भी होना चाहिए यदि असंतुलन के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता नहीं होती है। यह परिणाम सामाजिक संदर्भ निर्णय या सामाजिक न्याय निर्णय द्वारा प्राप्त किया जाता है।

21. वर्तमान वाद में, अपीलार्थी की आयु 35 वर्ष हो चुके हैं और वह मुकदमेबाजी में नौ वर्ष पहले ही हार चुकी है, लेकिन पति दिनांकित तलाक याचिका दायर 03.01.2018 को करने के बाद से इस अदालत या निचली अदालत के समक्ष पेश भी नहीं हुआ है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रतिवादी को अपीलार्थी के प्रति कोई भावनात्मक भावना नहीं है और वर्तमान तलाक याचिका दायर करने के बाद से, छह साल बीत चुके हैं और प्रतिवादी अपने वाद का बचाव करने के लिए इस अदालत के समक्ष नहीं आया और अपीलार्थी ने इस कारण से मामला दायर किया है कि उसे प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न और यातनापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। उसने दोहराया है कि वह वैवाहिक घर में शामिल हो गई है और फिर से उसने प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न और यातनापूर्ण व्यवहार के कारण वैवाहिक घर छोड़ दिया है और अपीलार्थी के पास पत्नी होने के नाते तलाक की याचिका दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और प्रतिवादी ने वैवाहिक घर में अपनी पत्नी की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया है। अपीलार्थी-पत्नी के प्रति प्रत्यर्थी-पति के उपेक्षापूर्ण रवैये से कोई इनकार नहीं कर सकता है और वैवाहिक जीवन के उद्देश्य से दोनों पक्षों को एक साथ रहना चाहिए और एक-दूसरे की भावनाओं को साझा करना चाहिए और निरंतर अलगाव की लंबी अवधि है और चूंकि अपीलार्थी की तारीख वर्तमान विविध अपील दायर करने तक वैवाहिक घर से चली गई है, आठ साल बीत चुके हैं। प्रत्यर्थी/पति अपने वाद का बचाव करने के लिए अदालत के समक्ष न तो उसने कोई सकारात्मक रवैया दिखाया है और अपीलार्थी/पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप अभी भी निराधार हैं। पारिवारिक कानून में प्रमाण के मानक की सख्ती से आवश्यकता नहीं है। यहाँ, न्यायालय को संभावना की प्रधानता पर वाद

के तथ्यों और परिस्थितियों को संतुष्ट करना होता है। यहां एक पक्ष/पत्नी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दहेज की मांग के लिए दूसरे पक्ष/पति के खिलाफ क्रूरता और यातना का आरोप लगाया और उसके पास वैवाहिक घर छोड़ने का कारण है और वह बातचीत के आधार पर 17.12.2014 को वैवाहिक घर में शामिल हो गई, लेकिन फिर से उसे दहेज की मांग के कारण परेशान और प्रताड़ित किया गया और वह स्थायी रूप से 20.03.2015 को वैवाहिक घर से चली गई और तब से वह वैवाहिक घर नहीं लौटी है। एक पत्नी होने के नाते अपीलार्थी ने तलाक की याचिका दायर करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। नोटिस जारी होने पर पति अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ और पति/प्रतिवादी ने तलाक की याचिका में लगाए गए आरोप के आधार का खंडन नहीं किया और एडब्ल्यू-2 के साथ खुद अपीलकर्ता ने अपने वाद को साबित किया कि वह अलग रह रही है और उसके पास अलग रहने का कारण है और पति ने अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया है। जहाँ तक तलाक की याचिका दायर करने का संबंध है, वह 03.01.2018 को दायर की गई है और तब से छह साल बीत चुके हैं।

22. वर्तमान वाद में, अपीलार्थी ने कहा है कि विवाह समारोह के बाद दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है।

23. **(2007) 4 एस. सी. सी. 511** में प्रतिवेदित **समर घोष बनाम जाया घोष** वाद को उद्घृत करना आवश्यक है, जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि न्यायालय को यह निर्णय करना है कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (आई - ए) के तहत के तहत क्रूरता क्या होगी। उपरोक्त निर्णय में एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश क्रूरता का निर्धारण करने में न्यायालय के दृष्टिकोण पर है। यहाँ जिस बात की जाँच की जानी है वह है संपूर्ण वैवाहिक संबंध, क्योंकि क्रूरता एक हिंसक कार्य या कृत्यों में नहीं हो सकती है, लेकिन किसी दिए गए वाद में हानिकारक निंदा, शिकायतों, आरोपों, ताने आदि से एकत्र किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के पैरा 41 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़

इंग्लैंड में वैवाहिक संबंधों में क्रूरता की परिभाषा पर भरोसा किया जो यहाँ पुनः प्रस्तुत की गई हैः-

> *"क्रूरता के सभी मामलों में सामान्य नियम यह है कि पूरे वैवाहिक संबंध पर विचार किया जाना चाहिए, और यह नियम विशेष महत्व का है जब क्रूरता में हिंसक कृत्य नहीं बल्कि हानिकारक निंदा, शिकायत, आरोप या ताने शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में जहां कोई हिंसा नहीं की जाती है, अधिनियमों की कुछ श्रेणियों या आचरण को बनाने की दृष्टि से न्यायिक घोषणाओं पर विचार करना आवंदनीय है, जैसा कि प्रकृति या गुण होने या न होने के रूप में आचरण जो उन्हें क्रूरता के बराबर सभी परिस्थितियों में सक्षम या अक्षम बनाता है; क्योंकि क्रूरता की शिकायत का आकलन करने में यह अपनी प्रकृति के बजाय आचरण का प्रभाव है जो सर्वोपरि महत्व रखता है। क्या एक पति या पत्नी दूसरे के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का सवाल है और पहले तय किए गए मामलों का बहुत कम, यदि कोई हो, मूल्य है। न्यायालय को पक्षकारों की शारीरिक और मानसिक स्थिति के साथ-साथ उनकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, और एक पति या पत्नी के व्यक्तित्व और आचरण के दूसरे के मन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से पति या पत्नी के बीच की सभी घटनाओं और झगड़ों पर विचार करना चाहिए; इसके अलावा, कथित आचरण की जांच शिकायतकर्ता की सहनशक्ति की क्षमता और उस क्षमता के प्रकाश में की जानी चाहिए जिससे दूसरे पति या पत्नी को पता हो।*

24. वर्तमान वाद में, आम तौर पर यह समझा जाता है कि जहां एक है, दूसरा चला गया है, वहां वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता है, जबकि पति और पत्नी वैवाहिक संबंध का विषय हैं और वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संबंध की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों

की आपसी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। वर्तमान वाद में, पति को किसी भी अवसर पर अपने वाद का बचाव करने के लिए भी नहीं पाया जाता है, तो व्यावहारिक और विवेकपूर्ण रूप से यह नहीं माना जा सकता है कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अपीलार्थी के भावनाओं एवं अनुभव दिखा सकता है। ऐसी स्तिथि में यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है। यहां तक कि वह अपनी पत्नी जो 20.03.2015 के बाद से शारीरिक रूप से अनुपस्थित के भावनात्मक बोझ को साझा नहीं कर सकता है है।

25. वर्तमान वाद में, संबंधित अदालत ने तलाक की डिक्री को अस्वीकार करने में बहुत ही अति तकनीकी और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया क्योंकि संबंधित अदालत ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि तलाक याचिका दायर करने की तारीख से या नोटिस जारी करने के बाद से, उसने अपने वाद का बचाव करने के लिए कदम नहीं उठाया है। यहां तक कि उसने भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर करके अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है और आदेश पारित करते समय संबंधित अदालत ने अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा की गई सामग्री और आरोप को ध्यान में नहीं रखा है और इसकी पुष्टि सटीक और संक्षिप्त तरीके से साक्ष्य द्वारा की गई है, लेकिन वाद का सार यह है कि अपीलकर्ता-पत्नी के पास अलग रहने का कारण है जिसका खंडन नहीं किया गया है और अपीलकर्ता के पिता/एडब्ल्यू-2 द्वारा इसे दोहराया गया है।

26. इस तरह, अपीलार्थी ने एक मामला बनाया है ताकि अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना द्वारा पारित दिनांकित 01.05.2023 और दिनांकित 09.05.2023 के डिक्री में हस्तक्षेप किया जा सके। तदनुसार, विवादित निर्णय दिनांक 01.05.2023 और डिक्री दिनांक 09.05.2023 को अपास्त किया जाता है। तदनुसार, अपीलार्थी और एकमात्र प्रतिवादी का 30.11.2024 को हाउस सं. 33, किदवईपुरी, थाना - कोतवाली, जिला - पटना में हुआ विवाह आज के दिन से विघरित किया जाता है। 2023 की वर्तमान एम. ए. संख्या 461 की स्वीकृति है।

27. कार्यालय को तदनुसार तलाक की डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहज़ाद/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।